संख्या: 15/2016 /951/ सत्रह - म- 2016, 6-9(III)/2014

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 10 जून 2016

विषय झींगा पालन योजनान्तर्गत वर्ष 2016- 17 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 12/2016/798/ सत्रह-म-2016, 6-9(III)/ 2014 दिनांक 03-05-2016 द्वारा झींगा पालन योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में 20 जनपदों के लिए रू0 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश में त्रुटिवश प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 लाख के सापेक्ष्य 50 प्रतिशत अर्थात रू0 10.00 लाख एवं कालम-6 में धनराशि रू0 0.50 हजार तथा नीलम अहलावत सचिव के स्थान पर नीलम अहलावत अनुसचिव अंकित हो गया है।

अत: निदेशक मत्स्य के पत्र संख्या- 248/नि0शा0 दिनांक 10-05-2016 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या- 12/2016/798/ सत्रह-म-2016, 6-9(III)/ 2014 दिनांक 03-05-2016 को निरस्त करते हुए झींगा पालन योजनान्तर्गत वर्ष 2016- 17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1000 हजार के सापेक्ष्य रू0 1000 हजार (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि 20 जनपदों के लिए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0सं0	जनपद	स्थापित की जाने वाली यूनिटों की संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)	प्रति यूनिट कुल लागत (रू0 हजार में)	50 प्रतिशत देय अनुदान धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	आजमगढ	02	1.00	100	50
2	मऊ	02	1.00	100	50
3	बलिया	02	1.00	100	50
4	गोरखपुर	02	1.00	100	50
5	महराजगंज	02	1.00	100	50
6	कुशीनगर	02	1.00	100	50
7	पीलीभीत	02	1.00	100	50
8	बिजनौर	02	1.00	100	50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

9	सहारनपुर	02	1.00	100	50
10	मुजफफरनगर	02	1.00	100	50
11	शामली	02	1.00	100	50
12	अलीगढ	02	1.00	100	50
13	आगरा	02	1.00	100	50
14	मैनपुरी	02	1.00	100	50
15	मथुरा	02	1.00	100	50
16	बहराइच	02	1.00	100	50
17	शाहजहॉपुर	02	1.00	100	50
18	रायबरेली	02	1.00	100	50
19	बाराणसी	02	1.00	100	50
20	गाजीपुर	02	1.00	100	50
	योग	40	20.00	-	1000

(कुल रू0 दस लाख मात्र)

1- उपरोक्त स्वीकृति लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित मापदण्डों / दिशा- निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।उक्त स्वीकृति धनराशि का किसी भी दशा मे किसी बैंक / पी0एल0ए0 में जमा नही की जायेगी । आंवटित धनराशि का सम्पूर्ण व्यय वित्तीय वर्ष 2016 -17 में किया जायेगा, जिसकी वित्तीय / भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ है/ हो रहा है।

2- यह योजना कृषकों की भांति मत्स्य पालकों की आय में वृद्दि के दृष्टिगत उल्लिखित जनपदो के प्रत्येक जनपद में 0.5 हे0 जलक्षेत्रों के निजी क्षेत्र /सामुदायिक क्षेत्र में पटटे पर आवंटित तालाब में संचालित करायी जायेगी । 0.5 हेक्टेअर जलक्षेत्र के एक इकाई में पूर्व में पाली गयी मछली के साथ-साथ 20,000 झीगा का बीज संचित कराया जायेगा ।

3- झींगे का बीज आई0सी0 ए0आर0 के केन्द्रीय संसाधनों (सी0आई0एफ0ई0) अथवा निजी क्षेत्र की झींगा हैचरी से क्रय कर हवाई मार्ग से यथा स्थिति सम्बंधित जनपदों के चयनित मत्स्य पालकों को मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा । जिस पर यातायात व्यय सहित 20,000 झीगा के बीज पर कुल रू0 20,000 का व्यय अनुमन्य होगा । झींगा फीड सरकारी अथवा गैरसरकारी क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत कम्पनियों / आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार आपूर्ति करायी जायेगी । 0.5 हेक्टेअर के एक यूनिट के लिए झींगा बीज के फीड हेतु रू0 30,000 व्यय किया जायेगा । इस प्रकार 0.5 हे0 के एक यूनिट के लिए झींगा बीज एवं फीड हेतु कुल रू0 50,000(रू0 पचास हजार) का व्यय होगा ।

4- झींगा पालन हेतु झींगा पालकों को 50 प्रतिशत अर्थात अधिकतम रू0 25,000 अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत की धनराशि जलभराव आदि कार्यो पर होने वाला व्यय झींगा पालकों द्वारा स्वयं के संसाधनों द्वारा वहन किया जायेगा अथवा आवश्यकतानुसार बैंक वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

5- झींगा पालन मे तकनीकी जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। झींगा पालकों को सम्बधित जनपदों के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा सप्ताहिक / पाक्षिक आधार पर निरीक्षणकर तकनीकी जानकारी कार्यस्थल पर सुलभ करायी जायेगी।

6- योजनान्तर्गत लाभाथियो का चयन निदेशालय मत्स्य द्वारा निर्धारित मापदण्डो / दिशा- निर्देशों के अनुसार सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की देखरेख एवं प्रभावी नियत्रंण में सम्पन्न कराया जायेगा ।

7- योजनान्तर्गत स्वीकृति धनराशि का उपयोग होने के उपरान्त समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा । योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता आवंछनीय होगी ।

2- उपरोक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016 -17 के अनुदान संख्या - 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन -आयोजनागत, 101- अर्न्तदेशीय मछली पालन, 04-मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0407- झींगा पालन, 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या – 1/2016 /बी0-1-746 /दस - 2016 -231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव।

संख्या 15/2016 /951 (1)/सत्रह-म-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा -परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- सम्बधित जनपद के कोषाधिकारी ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय।
5- सम्बंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।